



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—काण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ४९]

मई विल्ली सोमवार, मई १०, १९८२/वैशाख २०, १९०४

No. ४९]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 10, 1982/VAISAKHA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार विभाग

सार्वजनिक सूचना सं० २३/आईटी०सी० (पीएम) / ८२

नई दिल्ली, १० मई, १९८२

त्रिपथ । १९८१-८२ के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदान की गई येत
१. १३४ विविध (शृण महायता) की जापान अनुदान
महायता के ग्रन्तर्गत सार्वजनिक बोर्ड के आयातों के संबंध में
लाइसेंस दातें।

विसिल सं० ३०/आईटी०सी०/२३ (३१)/८२—१९८१-८२ के लिए जापान
सरकार द्वारा प्रदान की गई येत १. १३४ विविध (शृण महायता) की
जापान अनुदान महायता के ग्रन्तर्गत सार्वजनिक बोर्ड के आयातों के संबंध
में लाय होने वाली जैसी घातें हम सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी
गई हैं, वे जानकारी के लिए विविधित की जाती हैं।

मणि नागराजस्वामी, मृत्यु नियंत्रक
आयात एवं नियंत्रण

सर्वेतत्त्व मूल्य: मई २३/आईटी०सी० (पीएम) / ८२ कि. १०-५-१९८२
का परिशिष्ट १

जापान की सरकार द्वारा प्रदान लिए गए १९८१-८२ के लिए १. १३४
विविध (येत १. १३४,६९०,०००) (शृण नदारा) की जापानी अनुदान
महायता के ग्रन्तर्गत गारंजनिक बोर्ड के प्राप्तियाँ ही संबंध में लाइसेंस
दातें।

खंड १—सामान्य शर्तें

(१) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की येत १. १३४ विविध
जापानी अनुदान महायता भारत के अनावा और ५० सौ० बी० और विकास-
ग्रीन देशों के हृक में संगठित की गई है। तदनुसार, इस खंड के अधीन
विविधित की जाने आयी पथ वस्तुओं प्रीर उनसे संबंधित प्रामाणिक देवाकां अवधारण
और अनुबंध १ की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा
सकती है। ये देश इस अनुदान के अन्तर्गत पात्र सौत देश होंगे। इस अनु-
दान महायता के अधीन जो ग्राहक मद्द आयात की जा सकती है उनकी सूची
अनुबंध २ में दी गई है।

(२) याइसेम पर एक शीर्षक १९८१-८२ के लिए १. १३४ विविध
जापानी अनुदान महायता होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस
संकेत 'एम/जे-एन' होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण एवं
आयात लाइसेंस के अधिकारित पत्र में भी दृष्ट होंगे।

(३) एक खंड, जिनका प्रेषण सामान्य खंड प्रणाली के माध्यम से
किया जा सकता है, के अनिवार्य विवेची भूत्रा के किसी भी प्रेषित की
अनुमति आयात लाइसेंस के प्रते नहीं ही आयेगी। भारत अभिकर्ता के
कमीशन के प्रति फैर्स्ट भूत्रा भुगतान अभिकर्ता की भारतीय रूपां में जुकाम
चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मृत्यु के ही भाग होंगे और इसलिए
लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

(४) आयात लाइसेंस भागत-बीमा-भाषा के आधार पर १२ महीनों
की प्रारंभिक वैध प्रवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता
में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को सबढ़ लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क

करता चाहिए जो इस मामले में आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

(५) पक्षके आदेश अनुच्छेद १ में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र वेशों में स्थित विवेशी संभरकों को सागत और भाड़ा के प्राधार पर दिए जाने चाहिए और वे (जापान लाइसेंस जारी होने की तिथि से ४ महीनों की प्रवधि के भीतर) भवर लिविंग (टी-ए) आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। 'पक्षके आदेशों' का अर्थ विवेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन कदमों या कदमविवेशों से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आधिक की पुष्टि करने के बाद विवेशी संभरक द्वारा विधिक रूप से समर्थित हो या भारतीय आदेश और विवेशी संभरक द्वारा विधिक रूप से समर्थित हों। विवेशी संभरकों को भारतीय अधिकारियों के आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है।

(६) भारत महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इह गर्त का नव तक अनुपालन किया जाया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण प्रस्तावेज आदेश लाइसेंस जारी होने की तिथि से भारत महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुँच जाते हैं। यदि उपर्युक्त वैरा १(५) में यदा उल्लिखित पक्षके आदेश भारत महीनों के भीतर वैश्व कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो भारत महीनों के भीतर आदेश क्षयों नहीं दिए जा सके इह कारणों का उल्लेख करने पृष्ठ लाइसेंसधारी को आदेश लाइसेंस लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देता चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे मावेदों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पातना के प्राधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक भारत महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इह लाइसेंस के जारी होने की तिथि से ४ महीनों में प्रतिक के लिए यारी जारी हैं, तो ऐसे प्रस्ताव निरवाचन रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जानुपर्याप्त जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रयोग वालों की पातना के आधार पर विचार करेंगे और प्रथमा नियंत्रण वालीं अधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेतिर रखें।

पोत लघान के लिए आधिकारी नियि नियिका करने में इह बात का अन्य रखना चाहिए कि यह तिथि ३१-३-१९८३ के बाद की न हो। वैरा ३—संभरण ठेके का समझौता करने सम्बन्ध ध्यान में रखो जाने वाली विशेष बातें—

(१)(क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य ये या यू.एम.डी.लाइर या पौष्टि स्टेटिंग में एक येन, एक सेट या एक येनी से कवर की गिराव के बिना ही अधिक्यक्त होना चाहिए। और इनमें भारतीय अधिकारियों का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूपए में अकाता चाहिए। भारतीय रूपए या किसी अन्य नुमा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अधिक्यक्त नहीं होना चाहिए जहाज पर्यन्त निशुल्क भागत बीमा और भाड़ा बनराशि अलग अलग प्रदायित की जा सकती है परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का अर्थ वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में नियिक किए गए भाड़े का अर्थ वास्तविक अर्थ के अन्तिरिक्त देय बनराशि होगी।

(क) संविदा में तकर भावार पर अपर्याप्त वैश्व आक इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलघान वित्तवेशों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की अवस्था होनी चाहिए।

(ग) कदम आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण प्रयोग के बाद अप्रेजी में होनी चाहिए।

(२) आदेश लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति वी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आधिकारियों कार्य विभाग से आदेश लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व प्रत्युमोदन ले जेना चाहिए।

(२३) संभरक की प्रक्रिया

संभरक पात्र स्नोव डेशों का राइट्स होना या पात्र यों देशों में पंजीकृत और समाधिष्ट स्थायिक व्यक्ति होना।

वैरा ३ संभरण ठेकों में भिन्नतिहित शर्त विशेष रूप से समाधिष्ट होनी चाहिए—

३(१) १९८१-८२ के लिए १. १३४ नियिकन के अनुदान सदूचना से सम्बद्ध इस संविदा की अवस्था ६ फरवरी, १९८२ को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुमान की गई है।

३(२) विवेशी संभरकों को भुगतान उन 'भुगतान के लिए अधिकार-पत्र' (ए/पी) के माध्यम से लिया जाएगा जो १९८१-८२ के लिए जापानी अनुच्छेद सहायता के अधीन वैश्व आक इंडिया, टोकियो के नाम से नियावता एवं लेला परिवार नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आधिक नार्थ विभाग, यू.सी.ओ. बैंक नियिकन, पार्टिरायेंट एंट्राइट, नई दिल्ली, ११०००१ द्वारा जारी किया जाएगा।

३(३) विवेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा अंतर दूसरी और जापान सरकार द्वारा प्रोत्तेज हो।

३(४) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय बूतावाम टोकियो के परामर्श से पीलवान का अवस्था करने की तैयार है और उसके लिए सम्बन्धित माल की सम्पूर्णी के कार्यक्रम की भारतीय बूतावाम, टोकियो को सूचना देगा और प्रवेशित पात्र परिवहन के लिए कम से कम ६ सप्ताह से पहले ही भारतीय बूतावाम टोकियो को अधिसूचित करता हो जिसमें उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आदेशक लड़ जाहाज हों तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आदेशक इसे देने हुए प्रयोग पोनलदान के बाद जापानी संभरक को आदेशक को केवल सूचना में जिसके लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय बूतावाम, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

वैरा ४—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

४(१) जैसे ही आदेशों को अनिस्त स्पष्ट दे दिए जाने हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पाइयो, द्वारा विधिक रूपसंश्लिष्ट ठेके की भारत सरकार या सम्बद्ध पात्र संभरकों को भारतीय आदेशक द्वारा दिए गए का आदेश के साथ समझौता संभरक द्वारा विधिक स्पष्ट में पुष्टिकरण आदेश की भारत प्रतियों या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फॉर्म प्रतियों के गाथ अनुच्छेद ३ के प्रपत्र में 'ए/पी' जारी करने के 'आपेक्षन' की २ प्रतियों सहित संगत वैश्व आदेशक लाइसेंस की २ फॉर्म प्रतियों प्रति संक्षिप्त (टी-ए) आधिक कार्य विभाग विसंगतालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रतियों संविदा की विषयवस्तु या उसकी कीमत के आदेशक आदेशकों से उठाक्ष सभी संविदा भवित्वों के लिए भी जागू होगी।

४(२) यदि ठेके के वस्ताविज 'ए/पी' जारी घरने के लिए आधिक वित्त मंत्रालय, और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सभी पात्र जाने से वित्त मंत्रालय (आधिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग ठेके का अनुमोदन देना चाहिए और उपर्युक्त (१) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेला एवं लेला परिवार नियंत्रक, और भारत के राजतावाम, टोकियो और भारत में जापान के राजतावाम को भेजने अवश्य करेगा।

४(३) उपर्युक्त (२) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेला एवं लेला परिवार नियंत्रक, आधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पालियामेन्ट एंट्राइट, नई दिल्ली-११०००१ देंक आक इंडिया, टोकियो के लिए अनुच्छेद ४ के लिए विवेशी अभियोगों की भारतीय विभाग, जापानक, भारत में आदेशक के बैंक और जापान अनुभाग, आधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की पुष्टांकित की जाएगी।

(4) मृगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी) की प्राप्ति के बाद जैक और इंडिया, टोकियो जागान के सरकार, भारत के राजदूतावाय, टोकियो, आगामक के भारत में बैंक और स्थायी लेका एवं लेका परीक्षा नियन्त्रक को सूचना देते हुए, इस प्राप्ति की मूलता से संबद्ध को अवगत कराएं।

4(5) पांतश्वान अभावी करने के बाद विदेशी संभरण अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक और इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज मत्री पाप गए तो बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरण को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6) संभरक के लिए एसी जारी करने के लिए प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करने के लिए बैंक आॅफ इण्डिया, टॉकियो को देश बैंक खर्च, भारत में आयातक के मम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक आॅफ इण्डिया, टॉकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए जिसी तिर्फ़ास्ति द्वितीय जारी करने।

खण्ड ५—यापा अमा फट्टे का उत्तराखण्ड

5(1) मूल विनियम पीन परिवहन वस्तुतेज निरापदाद रूप से बैंक ग्रांफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक जो भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक [जो भ्रमुक्त न 3 के (प्रो) में उल्लिखित है] की शास्त्रा होंगी उम बैंक को दस्तावेजों के थे विनियम सेट केवल इस बात का नुसिक्षय कर लेने के बारे ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को बुकाई गई येन/ यू.एस.ओलर/पोष्ट स्टेटिक धनराशि के बारबर रूपया उन भारतीयों में जहां देने योग्य है व्याज के बच्चे सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक ग्रांफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वार्षिक रूपया जमा करने की नियम तक ही की प्रवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और दोष प्रवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं. 46 आई टी सी (पी.एन) / 76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेक्षा में जमा कर दिया गया है। व्याज दोमों दिनों, अर्थात् जिस विन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस विन सरकारी लेक्षे में रूपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देविय सार्वजनिक सूचना सं. 103 आई टी सी (पी.एन) / 76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-माइटीसी (पी.एन) / 74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों को येन यू.एस.ओलर/पोष्ट धनराशि के बारबर रूपए की गणना करने के लिए अनन्तर्वार्ता जाने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-नियति की गार्वजनिक सूचना सं. 0-8 आई टी सी (पी.एन) / 76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुद्रा नियंत्रक, आयात-नियति की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिवर्तनों, के माध्यम से सरकार द्वारा सम्बन्धित पर अधिसूचित की जाए। इस मस्बत्व में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का नुसिक्षय करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात वस्तावेज आयातकों को सौपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेक्षे में सही रूप से जाम कर दी गई है। लार्सेंसधारी का भी यह नुसिक्षय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से इस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेक्षे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस शीर्ष में उपर्युक्त रूपया जमा करना चाहिए वह 'के डिपोजिट्स एण्ट इवान्जेज- 843—मिलियड़ पौजिट्स—टिपोजिट्स फौर परसेजिस एडसेटा एडवाइज एवेंज मान्ट एड फ्राम गवर्नेंसें थ्रोक आयात कार एण्ड 1981-82 (येन 1,134 विलियन ग्राम्ब ऐड थ्राम—साहायता।

5(2). उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई विलासी में या स्टेट बैंक आँख इंडिया, तीम हुगारी, दिल्लो में बहुत हो पाये गए हैं।

जमा होनी चाहिए, या परि वह मुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक भारत ईडिया की किसी भाषा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयहूत बैंक (हुण्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक भारत ईडिया, तीस हजारी भाषा, दिनांक-6 (हुण्डी भाइक और प्राप्तक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184 आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68 सं० 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68 सं० 132-आईटीसी (पीएन), (71), दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पीएन)/78, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए बन प्रेषण करना चाहिए।

(3) सरकार द्वारा ऐसी माप किए जाने के बाबत मात्र जिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक की ऊपर नियांसित न होके से वह प्रतिरिक्षण अनुशासि सेवा जल्दी के तिमित जेजगा जो भारत सरकार द्वारा मार्गी जाए। जालाम के विभिन्न कालामों को भरते समय आवातकों/उपके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103 प्राइवेटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132 प्राइवेटीसी (पीएन)/71, विवाक 5-10-71 के विरा० 2 में नियांसित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 7-7-4 प्राइवेटीसी (पीएन)/74, विवाक 31-5-74 में भी नियांसित सूचना जालान के कालम "जन परेवण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्यापै" में नियन्त्राद रूप से नियंत्रित किए गए हैं। जालान जालान में नियन्त्रितिवाद और नियन्त्राद रूप से प्रस्तुत करें जाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र में प्रो
ग्रामपंक।

(क्र) ये न मुद्रा की बहु धनराशि जिसके संबंध में घटनार्थी गई परिवर्तन की दूर के साथ निलेप किए जाते हैं।

(ग) बिंदी संभरक को भगवान् कहने की शिक्षा

(८) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके प्रिये यह गिना जाएगा।

(इ) जमा की गई कल स्थनराशि।

(व्याज की गणना विवेती संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेव्र में ममतुल्य रूपया अमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए को जानी है।

उसके पश्चात् सी० ए० प० ए० ए० द्वारा आरी किए गए भूगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संर्वेते हुए प्लॉट और बोजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संतुलन करते हुए अजाता बाबत रखदा जमा करने का साक्ष्य देने हुए पंजीकृत डॉक द्वारा सी० ए० प० ए० ए० को खेजा जाना आहिए।

टिप्पणी: भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि उपरोक्त का निषेप बैंक प्रांत संक्षिया, टीकियों से अतायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोनलशाल वस्ताविकों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरवधा का से किया जाना चाहिए, और यह कि इसके सकाल बात सी ए०ए०ए०-८० घण्टा मध्याह्न अधिक कार्य विभाग), तर्हि खिलखी व सूचित कर दिया जाएगा।

5 (4) भारत में संबद्ध वैक प्रॉफ इंडिया, को लाइसेंस की पुष्टिमय नियमण प्रभि पर रुपवा नियमों की व्यवस्था का पृष्ठांक बन्द कर आहिए और अधिकार 'एस' प्रपत्र मारायी रिकॉर्ड वैक प्रॉफ व्यवस्थे सेजना आहिए।

पांड 6--विविध पार्ट

6(1) भाषात् साइसेस के उपयोग की हितों

भुगतान के लिए प्राप्तिकार पत्र जारी होने के बाद यात्राकर्ता को लदानों और उसके प्रभावों किए गए भुगतानों के संबंध में घोर जो पं

रदान होने वालों की उनके विषय में एक समिति रिपोर्ट सी० ई० ए० ए० ए० प्र०
...एक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, य० सी० औ० थै० विनियोग, संसद मार्ग
...विलली को भेजती चाहिए।

6(2) संभरकों की विशेष शर्तें अधिसूचित करता :

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से
...को अवगत करते हों कि विभाग, वित्त मंत्रालय, य० सी० औ० थै० विनियोग, संसद मार्ग
डाल सकती है।

6(3) विवाद

यह समझ लेता चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि
कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं
लेगी। थै० औ० ई० विनियोग, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्ण संभरक द्वारा पूरी की
जाने वाली भर्त साफ्टसॉफ 'भुगतान के नियम' के अधीन अनुबंध 1 में दर्शाई
जानी चाहिए। विवादों से निपटने की भर्ते ठेके की शर्तों में शामिल होनी
चाहिए।

6(4) विविध अनुदेश :

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ जाए होने वाले किसी मामले
या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1981-82 के लिए अनुदान सहायता
के अधीन सभी भारतीयों को पूर्ण फरसे के लिए भारत सरकार द्वारा समय-
समय पर जारी किए निर्देशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त
पासव करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपयुक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने
पर आयात-नियम (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की
जाएगी।

6(6) अनुबंध की सूची:

अनुबंध—1 पाल स्तोत वेशों देशों की सूची

अनुबंध—2 पाल पर्यवर्तनों की सूची

अनुबंध—3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन
करने का प्रक्रम।

अनुबंध 4—भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र

पाल स्तोत वेशों की सूची

(क) औ० ई० सी० ई० वेश

आस्ट्रेलिया

बेलिजियम

कनाडा

ऐनमार्क

फिनलैण्ड

कोस

जर्मनी संघीय गणराज्य

यूतान

प्राइसलैण्ड

आयरलैण्ड

इटली

जापान

लक्जस्यर्ड

वि. नीदरलैण्ड

न्यूजीलैण्ड

ताने

पुर्तगाल

स्लोवेनिया

स्लोवेनिया
स्लोवेनिया
तुर्की
दि.युनाइटेड किंगडम
और युनाइटेड स्टेट्स

(ज) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ग्र-1) नान-ओ० पी० ई० सी० विकासशील देश

1. प्राफ़ीका, उत्तरी सहारा

मिथ्र
मोराको
तुनीशिया

2. प्रफ़ीका, दक्षिणी सहारा

भारतीय
बोर्तवाना
बहराही
बोमेरान
केप बर्डी हीप समूह
केन्याय अफ़्रीकन गणराज्य
चाद
कमोरो हीप समूह
इथोपिया
जाबिया
कांगो, बमोह गणराज्य
इक्सोटोरियल गाईला
आना
गिनी
धाइवरी कोस्ट
कोलिया
लेसो थे
लाइबेरिया
मालीगासी गणराज्य
मलावी
माली
मारिलेनिया
मारीशिया
मोजाबिक
नाइजीरिया
पुर्णगाल गिनी
स्त्रियुनियन
रोडेशिया
रकाक्का
सेंट लुइसा और बेर (2)
सामोटोम ग्रिसाइट्ट

सेनेगाल
सेनिलीज
सियरा लिमोन
सोमालिया
सुडान
स्वाजीलैण्ड

टोरों प्रकार्स और इत्सास
टोमों
युगांडा
तामजारीनिया गणराज्य संघ
ग्रेवर बोल्टा

जाप्रेरे गणतंत्र
जामिया

3. अमेरिका—उत्तरी और केन्द्रीय :

बैहुगम
वारचांडोज
बेलाहज
बरगुडा
फोस्टारिका
क्यूबा
ओ मिनिकन गणतंत्र
एस साम्वडोर
गुआडेलोप
ग्वाटेमाला
हेटी ।
हायूरस
जैमेका
मार्टिनिक ब्यू
मेकिसिको
मीवरलैण्ड एनाटिलीज
निकारागुआ
पनामा
सेंट पियरी और गिब्रल्टान
ट्रिनिडाड और टोबागो
वेस्ट इंडीज (शाहा) एन० थाई० ह०
(क) सर्वाधित राज्य (1)
(ख) प्राधित राज्य (2)

- (1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, परनेडी पी द्वीप समूह।
- (2) निम्नलिखित द्वीपों महितः असेंशन, ट्रिस्टन डा इन एक्सेमिनिट्स, नाइट्रोनेल गक।
- (3) मेन समूह, भ्रम्बा, बोन्हरे, क्याकामों साहा, सेंट युस्टासिट, मेंट मारटिन (दक्षिण भाग)।

4. दक्षिणी अमेरिका :

अर्जेंटीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलंबिया
फाफलैण्ड द्वीपसमूह
फ्रांसीसी गिनी
गूयाना
पाराग्वे
पीरु
सुरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया :

बैहीन
इजरायल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिसियाई घरब गणतंत्र
यूनाइटेड घरब अमिरात
घरमन घरब गणतंत्र (3)
घरमन जनवादी डी० थार० (4)

6. दक्षिणी एशिया :

अफगानिस्तान

बांगलादेश

भूटान

बर्मा

मालदीव

नेपाल

पाकिस्तान

थ्रीनका

7. सुदूर पूर्व एशिया :

बुनई

हांगकांग

क्षमेर गणतंत्र

कोरिया गणतंत्र

लाओस

मकान्दो

मलेशिया

फिलिपाईन

बिंगापुर

ताइवान

वाइलैंड

तिपौर

वियनाम गणतंत्र

वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. प्रोसिनिया :

कोक द्वीप समूह

किंजी

गिल गिल्लेवर्ट और इलाइम द्वीप

फ्रांसीसी पोलिनेशिया (5)

नोक

न्यूकोलेझोनिया

न्यूहेबिसेस

हियू

पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)

पापुआ न्यू गिनी

सोलानन द्वीप समूह (त्रि)

टोंगो

बालिस और फतुना

परिचमी समाञ्जो

9. पूरोप :

साइप्रस

जिनाइटर

ग्रीक

माल्टी

स्पेन

तुर्की

युगोस्लाविया

- (1) मुख्य द्वीप एटिगुआ, ओमिनिका, रीनेडा, सेंट किल्ड (सेंट किल्डफो टोंको) नेविसध्रांगुह्सा, सेंट सुसिया और सेंट बिसेंट।
- (2) मेन आई लैण्ड, मोन्टेसे रेन, गमान, तुर्की और काइकेस और लिटिज वर्जिन द्वीपसमूह।
- (3) अजमन, तुष्वई, फूआइरह, शाम घल खमाह शरजाह और उम घल बवन।
- (4) घदन और बिपिश मल्लनत और अमीरात सहित।
- (5) सोसायटी प्राइ लैण्ड समूह (ताहिरी महिल) की शामिल करते हुए बास्ट्रो द्वीप समूह, दुग्रामोट, जाकियार शुप और मार्केस द्वीप समूह।
- (6) पैसिफिक द्वीप समूह का द्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्गेल द्वीप समूह और बेरिना द्वीप समूह (याम को छोड़कर)।

(ब-२) द्वां० पी० ई० सी० के सम्बन्ध या सहयोगी देश :

भर्जीरिया
बोलिविया
सीवियाई प्रदेश गणराज्य
गान्धार
नाइजीरिया
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ अफ़्रीका
देश
प्रैरान्त
ईराक
कुवैत
कोताड
सऊदी अरब
आबुधाबी
एडोमेशिया।

में वैक ग्रौफ़ इंडिया, टोकियो के लिए, भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए, हम प्राप्तको निम्नलिखित घोरे प्रस्तुत करते हैं:—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्या या औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके नामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि आया संविदा का निर्णय उपयुक्त स्थूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)
- (छ) यदि कोई हो तो भारतीय नप्ये में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की जनराशि।
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और विवांक
- (ञ) संभरक का नाम और पता
- (ट) वे भुगतान गते और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।
- (ठ) मुपुर्दी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि
- (इ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने समय तिथि जाने वाले वस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें। प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिक्कते हुए।)
- (ए) पोतलवान भनुदेश (बाह्नोतरण/पार्ट-णिपमेंट की भनुमति दी गई है या नहीं निर्विष्ट कीजिए।)
- (ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता
- (न) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई है। यदि हाँ, तो ऐसी संविदा की विवांक और मूल्य।

भवदीय

अनुबंध-३

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रारंभन-पत्र”

स०

विवांक

अनुबंध - ५

संख्या
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय,
प्राधिक कार्य विभाग,
मई दिल्ली, विनांक

सेवा में,

बैंक ग्रौफ़ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय : 1. 134 विलियन के लिए जापानी भनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।
प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-३-७९ को किए गए समझौते की शर्तों के प्रमुखार आपको एतद्वारा यथा संतर्ग घोरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए है) के भनुमार संबंधी भास

विषय :— 1981-82 के लिए 1.134 विलियन जापानी भनुदान सहायता येन के अधीन आयात से आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित भनुदान सहायता के अधीन आयात से आप कि आयात के संबंध में है संबंध संभरक के नाम

में.....ये भनराशि के मुगलान के लिए प्राविहृत किया जाता है।

2. भूगोल भूगलान के लिए प्राविकार पत्र (ए/पी) की पाबंदी के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टॉकियो और इस मंशालय को पष्ठोकित की जाए।

3. भूगलान के लिए प्राविकार पत्र की जरूरी के अनुसार भूगलान परिशिष्ट में यथा संकेतित यथात् दस्तावेजों के प्राधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आविर्त्त के लिए भाइंड सहित अवश्य किए जाने वाले बैंकिंग बाईंड में टॉकियो भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए नदान वस्तावेज के प्राधार पर आपके द्वारा कोई भी भूगलान किया जाता है सो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंशालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंशालय की विशेष अनुमति के बिना भूगलान के लिए प्राविकार पत्र के लिए कोई भी मंशालय जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भूगलान के लिए प्राविकार पत्र तक वैध रहेगा।

मंशालय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित नाम प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र में
दिनांक के मंदरमें।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक ऑफ़ इंडिया, टॉकियो, बॉन्च से वस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को यैम/यौम डालर/पौंड के दरावर सूचना जमा करने की अवस्था करें। विदेशी संभरकों की चुकायी गई भनराशि के दरावर सूचना की गणना भारतीय सूचना में 8-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भूगलान करने की निविक को यथा प्रतिवर्तन की सिविल दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भूगलान करने की निविक सरकार के देशों में सुन्दर सूचना जमा करने की नियत तक की प्रवधि के लिए मार्वेजनिक सूचना में 4-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत भी दर में व्याज भी सरकारी नेतृत्व में जमा कराना होगा। व्याज दों दिनों के लिए विदेशी आयातक की निविक को विदेशी संभरकों को भूगलान किया जाता है और वह नियत भी जिसको सरकारी नेतृत्व में रूपया निकाश किया जाता है। (इस दर में वटि कोई परिवर्तन किया जाया तो युग्मी सूचना दी जाएगी)। यह मुनिनिष्टत वर्त नेता चाहिए कि आयातक को सीमान्तक निवारी के लिए आयातक वस्तावेजों को मुन देट रिक्त जाने से पूर्व यह अन्वयित जमा की जानी है।

ये भनराशियाँ या तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, नई शिल्पी या स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया नीग हजारी, शिल्पी में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी शाखा या हसकी अनुबंधी मंशालयों या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, नीग हजारी शाखा, विल्सनी-6 (प्रावेशित और आदाना) के नाम में और उनको

वेय दरोंनी हुंडी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना में 23-आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-68, सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 की जारी की थीर दिलाया जाता है। लेकिंग योर्पे जिसमें भनराशि जमा की जाएगी वह 'के हिपोजिट्स एंड एक्सीस-843 निविल हिपोजिट्स—हिपोजिट्स फार परवेसिस एट्सेट्रा ब्राइट—परवेसिस ग्रांट एंड फ्राम दि गवर्नमेंट ऑफ़ आयात फार 1981-82 (येन 1. 134 विलियन ग्रांट एंड ब्रेट रिलीफ़)'

जिन मामलों में तुल्य रूपया रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, नई शिल्पी या स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना में 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें जालन की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ऑफ़ इंडिया, टॉकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देने हुए अधेशण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित परे पर भेजी जाएगी :—

महायता लेखा तथा नेत्रा परीक्षानियंत्रक, वित्त मंशालय (भार्यक कार्य विभाग) पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक विल्डिंग, संपद मार्ग, मई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रूपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्णनी हुंडी द्वारा प्रेषित करता है उनकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जाती रहती है। सभी मामलों में व्याज की चुकायी गई अन्य व्याज की गणना की गई है और उनके साथ जटा किंवदं तुल्य रूपया की गई है अधिकारी इस विभाग को भेजना चाहिए।

समृद्धार संभरकों के बैंकर के बर्डी सहित यवि कोई ही तो, बैंकिंग बर्डी और बैंक ऑफ़ इंडिया, टॉकियो शाखा के इन्यू बर्डी बैंक और बैंक ऑफ़ इंडिया, टॉकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टॉकियो

5. वित्त मंशिय (टीए) शाखा, वित्त मंशालय, ऑफिस कार्य विभाग, नई विल्ली।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 23-ITC(PN)/82

New Delhi, the 10th May, 1982

Subject :—Licensing condition in respect of public sector imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.134 Billion (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan.

File No. IPC/23(31)/82.—The terms and conditions governing the issuance of import licences in respect of public sector imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.134 Billion (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYAN SWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 23-ITC(PN)/82 Dated the 10-5-1982

Licensing Conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.134 Billion (Y 1,134,696,000) (Debt Relief) for 1981-82 Extended by the Government of Japan

Section I.—General Conditions :

(i) The Japanese Grant Aid of Yen 1.134 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries except India. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured

under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I(iii) The licence will bear the superscription "Yen 1.134 billion Japanese Grant Aid for 1981-82". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iv) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(v) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(vi) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(vii) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1983.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract :

II(i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior appro-

val of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(iii) Eligibility of Supplier :

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III :

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 6th February, 1982 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.134 billion for 1981-82 "and will be subject to the approval of Government of India".

III(ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1981-82.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Government of India :

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Japan Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV(v) The foreign supplier shall, after affecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US\$/Pound sterling Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 9% per annum for the first thirty days and at 15% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 193-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US\$/£ Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1981-82 (Yen 1.134 billion Grant Aid—Debt-relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan.

The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- Date of payment to the foreign supplier.
- The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions :

The licensee shall promptly comply with directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1981-82 from Japan.

VI(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act)

VI(vi) List of Annexures :

Annexure-I—List of eligible source countries

Annexure-II—List of eligible commodities

Annexure-III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

ANNEXURE I

List of eligible source countries

A. OECD Countries :

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the United Kingdom and
the United States

B. Developing Countries and Territories :

(b1) Non-O.P.E.C. Developing countries

I. AFRICA, North of Sahara :

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara :

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's
Republic of Dahomey (1)
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terror. Afars and
Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
 (2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Cunha, Inaccessible, Nightingale, Gough.
 (3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Martin (Southern Part).

III. AMERICA, North and Cent.

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre and Miquelon
Trinidad and Tobago
West Indies (Br.) n.e.

(a) Associated States (1)
 (b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South :

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East :

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South :

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East :

Borneo
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Vietnam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

(1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis, Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
 (2) Main islands : Montserrat, Gayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
 (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
 (4) Including Aden and various sultanates and emirates.

VIII. OCEANIA :

Cock Islands
Fiji
Gilbert and Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (U.S) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE :

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta S
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC :

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II**Eligible Commodity List**

1. Rolls
2. Steel including special steel and alloy steel
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors.
4. Chemicals
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Venture.
6. Components, attachments and spares for power tillers
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
8. Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India.
9. Machinery and equipment for the Oil and Natural Gas Commission Projects.
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands; Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

ANNEXURE III**"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"**

No.

To The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject :—Import from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 1.134 billion for 1981-82.

Sir,

In connection with the import of _____ from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and Address of the supplier.
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transhipment/part shipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No., date and value of such contract.

ANNEXURE IV

No.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To
The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 1.134 billion Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen _____ to M/s. _____ (as per details given in the Appendix)

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India, Tokyo Importers Bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. The A/P will remain valid upto _____

Yours faithfully,

Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____

2. Importer's Banker _____ they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen/US \$/£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITCPN/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notice as may be issued from time to time. Interest @ 9% per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is

made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 23-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN) 74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1981-82 (Yen 1.134 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch; including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)